साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 17-23 अक्टूबर, 2022, वर्ष-8, अंक-28

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

## पीएम मोदी बोले-भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा

# श्री महाकाल लोक अलौकिक-अविस्मरणीय, अविश्वसनीय

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का लाभ न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व एवं समूची मानवता को मिलेगा। उज्जैन में श्री महाकाल लोक की स्थापना इसी की कड़ी है। यह काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख है। उज्जैन आज भारत की सांस्कृतिक अमरता की घोषणा और नये कालखंड का उद्घोष कर रहा है। हमारे लिए धर्म का अर्थ कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प, विश्व का कल्याण एवं मानव मात्र की सेवा है। हमने आजादी के पहले जो खोया था, उसकी आज पुनर्स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री गत दिवस उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल लोक दिव्य है। यहां सब कुछ अलौकिक, अविस्मरणीय एवं अविश्वसनीय है। महाकाल की आराधना अन्त से अनन्त की यात्रा है, आनं द की यात्रा है, इससे काल की रेखाएं भी मिट जाती हैं। महाकाल लोक आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता और सांस्कृतिक ऊर्जा की चेतना प्रदान करेगा।

- शिवराज ने हृदय से किया अभिनंदन, बोले-प्रलय के प्रहार से मुक्त महाकाल नगरी
- उज्जैन में पूरे ब्रह्माण्ड की ऊर्जा को ऋषियों ने प्रतीक रूप में समाहित किया
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक को राष्ट्र को किया समर्पित

### महाकाल की नगरी उज्जैन

पीएम ने कहा कि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन वह नगरी है, जो प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। प्रलयो न बाध्यते, तत् महाकाल पूज्यते। उज्जैन न केवल काल गणना एवं ज्योतिषिय गणना का केन्द्र है, अपितु यह भारत की आत्मा का केन्द्र भी है। यह पवित्र सात पुरियों में एक है। यहां भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की।

### कण-कण में आध्यात्म

उज्जैन के क्षण-क्षण में इतिहास, कण-कण में आध्यात्म और कोने-कोने में ईश्वरीय ऊर्जा है। यहां कालचक्र के चौरासी कल्पों के प्रतीक चौरासी महादेव, चार महावीर, छह विनायक, आठ भैरव, अष्टमातृका, नौ ग्रह, दस विष्णु, ग्यारह रूद्र, बारह आदित्य, चौबीस देवियाँ एवं 88 तीर्थ हैं। इन सबके केन्द्र में कालाधिराज महाराज विराजमान हैं।

### भारत में ही सभ्यता के सूर्य का उदय

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में ही सभ्यता के सूर्य का उदय हुआ। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम् एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः भी है। हमारा संदेश विश्व कल्याण का है। भारत के इसी सन्देश को स्वामी विवेकानन्द ने सारी दुनिया को दिया। एक नरेन्द्र ने जो किया दूसरा नरेन्द्र आज उसे पूरा कर रहा है। हमारा योग, उपनिषद, गीता-ज्ञान, आयुष वे दुनिया में लेकर गए। आज नरेन्द्र मोदी गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। 2016 के सिंहस्थ में विचार महाकुंभ भी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। विचार महाकुंभ में 51 अमृत बिन्दु निकले, जिनमें से एक श्री महाकाल लोक की स्थापना का कार्य भी था। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस कार्य की शुरुआत की गई। वर्ष 2018 में केबिनेट ने इसे स्वीकृति दी, वर्ष 2019-20 में यह कार्य मंद हो गया, लेकिन वर्ष 2020 के बाद तेजी से हुआ। आज इसका लोकार्पण हो रहा है। भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हैं, थोड़ी-सी पूजा से वे प्रसन्न हो जाते हैं, जिसे दुनिया दुकराती है, उसे अपनाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को अमृत दिया और स्वयं जहर पिया।

## मुख्यमंत्री ने कहा-मेरे पास नहीं आनी चाहिए शिकायत

# प्रदेश में पर्याप्त यूरिया-डीएपी किसानों से संवाद करें अधिकारी

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के कुछ जिलों से आ रही खाद की कमी की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से खाद के भंडारण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के बाद कहा कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है। ऐसे में अधिकारी उन किसानों से संवाद करें, जो खाद नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। संवाद में देरी न हो और ऐसी शिकायतें न आएं। मुख्यमंत्री ने मार्कफेड को जिलों में अधिक विक्रय केंद्र बनाने और खामी हों तो व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का खाद आपूर्ति में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से भी समय-समय पर चर्चा होती है और प्रदेश को उर्वरक की आपूर्ति बिना बाधा होती रही है। बैठक में तय किया गया कि विक्रय केंद्र बढ़ाए जाएंगे और स्कंध खत्म होने से पहले भंडारण करेंगे। इसकी लगातार समीक्षा भी की जाएगी।

### खाद पर्याप्त मात्रा में

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को भरोसा दिलाना जरूरी है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खाद संकट की आशंका के आधार पर अनावश्यक संग्रहण न करें। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछले साल इस तरह की शिकायतें नहीं आई थीं। संयुक्त प्रयासों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं मिल कर मानीटरिंग कर रहे हैं। खाद वितरण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट जरूरी है। संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

### उर्वरकों की रेक मिल रही

कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद है। प्रदेश की मांग पर केंद्र सरकार से उर्वरकों की रेक लगातार मिल रही हैं। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सहकारिता क्षेत्र में यूरिया, डीएपी उर्वरकों की 70 प्रतिशत से कम मात्रा का उठाव किया है। जिला विपणन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगद विक्रय केंद्र पर खाद के इच्छुक किसानों के लिए व्यवस्थित प्रबंध करें।

### अप्रैल से अब तक आया खाद

प्रदेश में अप्रैल से लेकर 11 अक्टूबर तक यूरिया 19.09 लाख टन, डीएपी 9.80 लाख टन, एनपीके 3.42 लाख टन और एसएसपी 8.58 लाख टन उपलब्ध है। पिछले साल की तुलना में इस साल आलोच्य अवधि में प्रत्येक उर्वरक का अधिक भंडारण हुआ है। जबकि विक्रय पिछले साल से कम है और शेष स्कंध की मात्रा यूरिया 2.51 लाख टन, डीएपी 1.98 लाख टन, एनपीके 1.31 लाख टन, एसएसपी 3.50 लाख टन है। इस महीने 11.84 लाख टन उर्वरक मिलने की उम्मीद है।

## इंदौर में बोले नरेंद्रसिंह तोमर-केंद्र और राज्य इस पर कर रहे काम

# एक साल में कृषि और किसानों को डिजिटल तकनीक से मिलेगा लाभ

इंदौर। जागत गांव हमार

केंद्र तेजी से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रहा है। हम राज्यों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें फसलों का डाटा, किसान की जमीन, कब किस राज्य में कौन सी फसल बोई जा रही है और कहां किस फसल को क्या दाम मिल रहे हैं, जैसी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। नई व्यवस्था कृषि और कृषकों के लिए बेहद कारगर होगी। इससे फसलों के सही दाम नहीं मिलने जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक खास चर्चा में कही। वे मांडू में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब तक फसलों का डाटा इकट्ठा करने का कोई बेहतर मैकेनिज्म विकसित नहीं हो सका था। इस वजह से तकनीक का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। इसमें देश के किस हिस्से में कौन सी फसल कितने हेक्टेयर में बोई गई है, यह जानकारी सभी को मिल सकेगी। इससे कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को सही जानकारी दे सकेंगे कि कौन सी फसल से फायदा या नुकसान होगा। इस तकनीक से किसान की पहुंच बाजार तक भी आसानी से हो जाएगी। यह पूरा प्लेटफार्म तैयार करने के बाद एग्री स्टार्टअप क्षेत्र में काम करने वाले भी कृषि क्षेत्र में बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। इससे उत्पादन, फसल, मौसम, नुकसान जैसी जानकारियां सटीक और त्वरित मिलने लगेंगी। एक साल में यह कार्य करने लगेगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी भी राज्यों को ही सौंपी जाएगी।

### फूड प्रोसेसिंग में हो रहा बेहतर काम

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में बेहतर कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। प्रदेश के लोगों को आगे आकर इसका लाभ उठाना चाहिए। इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट ही एक लाख करोड़ का है। प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के दौर में फूड प्रोसेसिंग बेहतर परिणाम देने वाला क्षेत्र है।

## भोपाल से 46 किमी खजुरिया कलां गांव बदहाली का शिकार, गांव वालों में पनप रहा आक्रोश

# सांसद प्रज्ञा का 'आदर्श' गांव 'अनाथ'

-ग्रामीणों ने अपनी सांसद से 7 मांगें की थीं, एक भी पूरी नहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

सात साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी ताकि गांवों की सूरत बदले। यहां सड़कें सुधरें, पक्की नालियां बनें, सीपेज सिस्टम बेहतर हो, साफ-सफाई रहे आदि। लेकिन, ऐसा हो नहीं रहा है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गोद लिए गांव खजुरिया कलां की तस्वीर एकदम उलट है। यानी गोद लेने के बाद भी अनाथ की तरह पड़ा है। गांव के ही लियाकत, सुरेश गौर, साबिर का कहना है कि एक जनवरी 2021 को सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस गांव को गोद लेने की घोषणा की, लेकिन इसका भूमिपूजन करने में उन्होंने छह महीने लगा दिए। 12 जुलाई को सांसद ने विधिवत गांव गोद लिया। हमने 7 मांगें रखीं, लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। इन पौने दो साल में सिर्फ एक यात्री प्रतीक्षालय बना है, जिस पर उनकी बड़ी सी फोटो लगी है। यहां सड़कें टूटी हैं, स्कूल जर्जर है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट बेकार पड़ी हैं, नदी घाट के सौंदर्यीकरण का एक भी काम नहीं हुआ। गोद लेने के बाद सांसद सिर्फ दो बार गांव आईं, जबकि उसके पहले तीन बार आईं थीं। सीहोर जिले का खजुरिया कलां गांव भोपाल से 46 किमी दूर है, जहां 3860 आबादी में 2284 वोटर हैं।

### सौंदर्यीकरण का बजट भी लैप्स

पंचायत चुनाव से पहले 15 लाख रुपए में नदी घाट के सौंदर्यीकरण के लिए मंजूर हुए थे, लेकिन तत्कालीन सरपंच व पंचायत अफसरों में राशि को लेकर मतभेद हो गया। नतीजा ये हुआ कि आचार संहिता लग गई और बजट लैप्स हो गया।

### गांव में सभी काम हो रहे

वहीं सीईओ हर्ष सिंह का दावा है कि गांव में पीएम आवास, स्वच्छ भारत, मनरेगा व पेंशन के काम चल रहे हैं। सांसद का काम समन्वय का है। उनके प्रपोजल पर काम जारी है।

### हैंडपंप भी सूख गए

मौजीराम ने बताया कि गांव में 1995 में पानी की टंकी बनी थी, जो आज तक पूरी नहीं भर पाई। कभी बिजली नहीं तो कभी मोटर खराब। नल-जल योजना के तहत जाजन खेड़ी में टंकी बनी है, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाई। यहां हैंडपंप भी सूख चुके हैं।

### जर्जर स्कूल

गांव में 10वीं तक स्कूल है। यहां 200 बच्चे पढ़ते हैं। छत में बड़े-बड़े छेद हैं। यहां गेट, जालियां चोरी हो गई हैं। स्कूल का एक हिस्सा टूट चुका है। चाहरदीवारी बनवाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

### गांव की दरकार

स्कूल के मैदान की बाउंड्रीवॉल। लागत करीब 25 लाख रुपए। गांव में पक्की नालियों का निर्माण। लागत करीब 92 लाख रुपए। पारवा नदी पर घाट का सौंदर्यीकरण। लागत करीब 15 लाख रुपए। मेहंदीवाली मेन सड़क से गौरीलाल के खेत तक एक किमी की खेत सड़क। लागत 14 लाख रुपए। पूरे गांव में पांच किमी की सड़कें चाहिए। लागत करीब 75 लाख। स्ट्रीट लाइट चाहिए। बजट 2.10 लाख रुपए की दरकार है।

### हर सांसद एक गांव गोद लेगा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा। लेकिन शर्त ये है थी कि जो सांसद जो भी गांव चुनेंगे वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। पीएम ने कहा था, इस योजना से हर सांसद के नेतृत्व और प्रयत्न से एक साल में 800 गांवों का कायाकल्प होगा।

ओपन जिम का बजट स्वीकृत हुआ है। नाला गहरीकरण का काम हुआ है। गांव में गेट बनवा रहे हैं। इसका प्रस्ताव भेजा है।
- सिद्धगोपाल वर्मा, सीईओ जपं, सीहोर

## 2022-23 से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले पर होगा असर

# वेटरनरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने छात्रों को देनी होगी 50 फीसदी ज्यादा फीस

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में संचालित वेटरनरी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक सत्र से ज्यादा फीस भुगतान करनी होगी। वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर ने अपने डिग्री, डिप्लोमा समेत पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रमों की फीस में 50 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। इसका असर 2022-23 से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की फीस पर होगा। प्रदेश में तीन वेटरनरी जबलपुर, महू, रीवा और पांच डिप्लोमा कालेज जबलपुर, रीवा, मुरैना, भोपाल और महू हैं, जिसमें हर साल लगभग एक हजार से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिग्री और डिप्लोमा की सीटों में इजाफा करने के साथ ही फीस में भी इजाफा किया है। वेटरनरी कौंसिल आफ इंडिया के मापदंड को पूरा करने के लिए विवि प्रशासन ने हाल ही में तीनों वेटरनरी कालेज में तकनीकी पदों में भर्ती की। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद भरे हैं। अब इन्हें वेतन देने और इनके अन्य भत्तों का भुगतान करने विश्वविद्यालयों को हर माह एक करोड़ की अतिरिक्त राशि चाहिए। जल्द ही विवि प्रशासन डिप्लोमा के स्वीकृत तकनीकी पदों को भरने जा रहा है।

### किसकी-कितनी बढ़ी फीस

» बैचलर आफ वेटरनरी साइंस पाठ्यक्रम में पहले हर साल लगभग 50 हजार फीस थी, जो अब लगभग 75 हजार हो गई।

» डिप्लोमा आफ वेटरनरी साइंस पाठ्यक्रम में पहले हर साल लगभग 33 हजार फीस थी, जो अब 55 हजार हो गई।

» वेटरनरी पीजी और पीएचडी की फीस में भी लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

### पुराने विद्यार्थियों को मिली राहत

विवि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्हें पुरानी फीस ही देनी होगी, जिससे छात्रों में खुशी है। हालांकि नए सत्र में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों को अब ज्यादा फीस देकर कोर्स करना होगा।

विश्वविद्यालय ने सभी पाठ्यक्रमों की फीस में इजाफा किया है। नए सत्र से प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों को ही बढ़ी फीस देनी होगी। हालांकि पुराने विद्यार्थियों की फीस में कोई बदलाव नहीं किया है।
-डॉ.एसके जोशी, कुलसचिव, वेटरनरी विवि, जबलपुर

**बोर्ड की सहमति, अब होगी लागू**

वेटरनरी विश्वविद्यालय की बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों ने फीस वृद्धि को लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सभी ने एक मत से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दरअसल, विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई, तब से अब तक किसी भी वेटरनरी पाठ्यक्रम की फीस नहीं बढ़ाई गई। पहली बार वेटरनरी प्रशासन ने डिग्री से लेकर डिप्लोमा, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम की बढ़ाई गई फीस से सीधे 50 से 60 प्रतिशत तक फीस बढ़ गई है। इधर, विवि प्रशासन के मुताबिक फीस वृद्धि करने की मुख्य वजह विश्वविद्यालय के बढ़ते खर्चे हैं।

## नवाचार के मिले अच्छे परिणाम, अब पूरे प्रदेश में लागू

# हरदा, इंदौर और डिंडोरी में खुलेंगी सायबर तहसील

भोपाल। जागत गांव हमार

सीहोर एवं दतिया जिले से सायबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में लागू किया जा रहा है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सायबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। मंत्री ने कहा कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। हमने अविवादित नामांतरण /बटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए सायबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में सायबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण/ बटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन कर के ऐसे अविवादित नामांतरण/बटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम है।

### दूसरे राज्य कर रहे योजना का अध्ययन

मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश के सायबर तहसील की परिकल्पना इतनी बेहतर है कि अन्य राज्यों के राजस्व महकमें का दल इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के अध्यन के लिए मध्यप्रदेश आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के दूसरे राज्य भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश की सायबर तहसील के कान्सेप्ट को लागू करेंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की सफलता का आकलन करने के लिए हम 6 महीने तक इसके परिणाम का अध्ययन करेंगे और फिर पूरे प्रदेश में लागू करेंगे।

जागत गांव हमार

- अधिकारियों को दिए प्रभावित फसलों का सर्वे करने के निर्देश
- किसानों को सर्वे के आधार पर किसानों राहत राशि दी जाएगी
- प्रदेश में बारिश के चलते किसानों की फसलों को हुआ नुकसान
- चना सरसों, सोयाबीन और मूंगफली की खेती पर गहराया संकट

# आहत किसानों को मिलेगी राहत

## शिवराज बोले-बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों का सरकार देगी मुआवजा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने किसानों पर कहर ढाया है। बारिश का फसलों पर भी खासा असर देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से मालवा के किसानों की नाक में दम हो गया है। सोयाबीन की फसल खेत में रखी है, लेकिन बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। बर्बाद हुई फसलों से किसान पूरी तरह हताश नजर आ रहे हैं। वहीं किसान मुआवजे की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने जहां आम जन जीवन को प्रभावित किया है, तो वहीं किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। रतलाम में किसान अब मौसम की दोहरी मार झेल रहे है। बारिश ने किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया। सोयाबीन की फसल पकने के बाद खेतों में पानी भर जाने से फसल सड़ चुकी है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल खराब हो चुकी है, अब वे जल्द ही सर्वे कराने के साथ सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसम बरसात से कई जगह किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है। लेकिन वे चिंता नहीं करें। प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल फसलों के नुकसान का सर्वे आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे कर, क्षति के आकलन के आधार पर किसानों राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। किसानचिंता न करें, राज्य सरकार उनके साथ है। क्षति की भरपाई की जाएगी। प्रभावित किसानों को संकट से उबारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

### शिवपुरी के किसान चिंतित

शिवपुरी जिले में कई तहसीलों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वर्तमान में सरसों, सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं भारी बारिश से कहीं फसल भीग गई है तो कहीं फिर से अंकुरित हो गई है। शिवपुरी में सरसों की फसल को जिन किसानों ने सीडिल करके बोवनी की थी उनकी फसल को नुकसान हुआ है, क्योंकि सीडिल के द्वारा बीज और खाद को मिक्स करके ट्रैक्टर से बोवनी की जाती है, जिससे बीज अधिक गहराई में पहुंच जाता है।

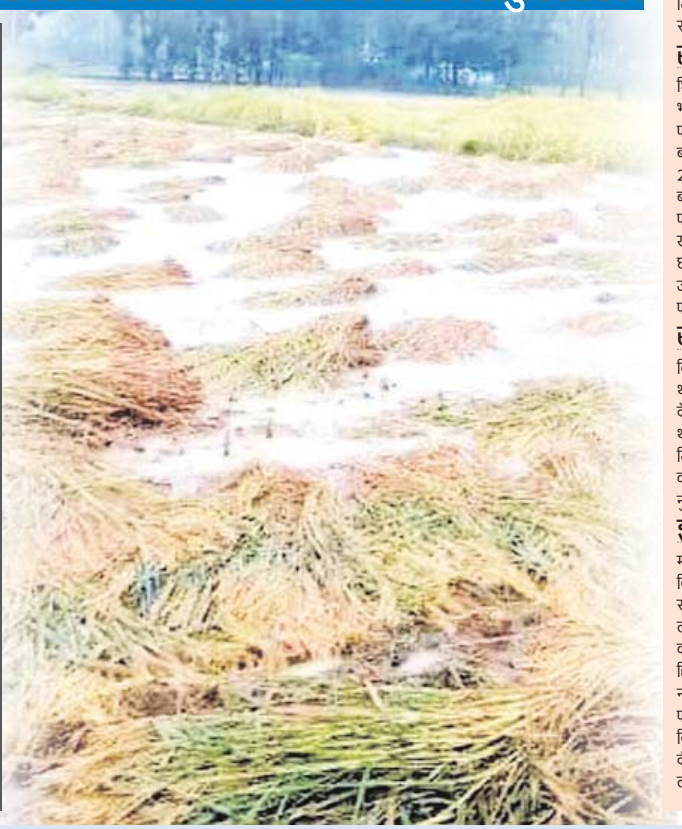

### बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा

फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश अधिक होने से खेतो में पानी भर गया हैं अब बीज जमीन में और अधिक गहराई पकड़ लेगा जिसके कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। हालांकि सरसों की फसल के लिए जिन लोगों ने बीज को खेतों में फेंक फेंक कर बोवनी की है उन किसानों को इस बारिश से फायदा होगा। क्योंकि यह है जमीन में अधिक गहराई नहीं पकड़ पाता है, जिसके चलते बीज जमीन के हल्का सा अंदर रहता है जिससे यह बीज अंकुरित हो सकता है।

### सोयाबीन की फसल खराब

शिवपुरी में सोयाबीन की फसल भी खराब हुई है भारी बारिश के चलते किसानों की सोयाबीन की फसल कटी हुई खेतों पर रखी हुई थी। अब बारिश के चलते वह फसल भी खराब हो गई है। 28-29 सितंबर की दरमियान शिवपुरी में बारिश हुई थी, जिसके चलते सोयाबीन की फसल भीग गई थी। किसानों ने सुखाने के लिए खेतों पर ही सोयाबीन की फसल को इकट्ठा कर छोड़ दिया था, जिससे कि फसल धूप से सूख जाए, लेकिन अब फिर से हुई बारिश के चलते फसल खराब हो गई है।

### खेतों में रखी मूंगफली बर्बाद

किसानों की मूंगफली जो कटी हुई खेतों में रखी थी वह भारी बारिश से भीग गई है आपको बता दें कि जिन लोगों ने मूंगफली की कटाई नहीं की थी, उनका बीज फिर से अंकुरित होने लगा है जिसके चलते मूंगफली को नुकसान हुआ है। वहीं खेतों में निकली पड़ी मूंगफली को भी नुकसान हुआ है।

### इंदौर में सोयाबीन चौपट

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर के किसानों ने बताया की उनके पूरे खेत में सोयाबीन की फसल पक गई थी, लेकिन लगातार बारिश ने अच्छी भली फसल को खराब कर दिया है। किसानों ने 8-10 हजार रुपए क्विंटल का बीज लगाया था। महंगे खरपतवार नाशक और कीटनाशक का छिड़काव किया था। फसल पिछले साल के मुकाबले बेहतर और उम्दा दिख रही थी, लेकिन बारिश ने सब खराब कर दी। अब किसानों के खर्च निकालने तक के लाले पड़ रहे हैं।

### बह गई लाखों की फसल

कई किसानों के फसल कट गई थी, लेकिन खेतों में रखी फसल में बारिश के कारण पानी लग गया और फसल अब सड़ने लगी है। वहीं जिन किसानों की फसलें नहीं कटी है वे ना तो फसल को काट पा रहे हैं ना ही खेतों से जल निकासी संभव हो पा रही है। देपालपुर, हातोद के साथ सांवेर के इलाकों में बारिश के कारण खेतों में सोयाबीन डूब रही है और तालाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। अब जितनी भी बारिश हो रही है उसका पानी खेतो में भरा हुआ है।

### किसान बोले, मुआवजा दिलाए सरकार

देपालपुर तहसील के गांव तलावली के किसान राजेश बताते हैं कि इस समय हुई बारिश ने हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। 10 हजार रुपए क्विंटल के बीज और लाखों की महंगी दवाइयां छिड़की गई थी। पिछले सालों के मुकाबले इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन हमारा खर्च तक निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन और सरकार को हमारे खेतों के सर्वे कर हमें मुआवजा दिलवाए। इधर, रतलाम में पिछले तीन दिनों में प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि रविवार को मौसम साफ रहा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 11 से 15 अक्टूबर के बीच फिर से बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन एक्टिव हो सकता है और इसकार असर देश के पश्चिमी भू-भाग पर पड़ेगा।

### होगा सर्वे, चिंता ना करें किसान

रतलाम कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को खराब फसलों के सर्वे के लिए निर्देश दिए हैं। असामयिक बारिश के दृष्टिगत फसल क्षति की सूचनाएं मिली हैं। शासन व प्रशासन किसानों के साथ है। सभी को जल्द राहत प्रदान को जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार, जिन किसानों ने सोयाबीन काट रखी थी, उन्हें अचानक हुई इस तेज बारिश में नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि लंबे समय की फसल को इस बारिश से लाभ है।

# जीवों और फसलों के विनाश का कारण बन सकता है प्रकृति का बदलता मिजाज

**डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह**
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिण्ड)

प्रकृति का बदलता स्वरूप प्रलयकारी सिद्ध हो रहा है। साल दर साल अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ती चली जा रहीं हैं। दुनियां के अधिकांश देशों में कुदरत के प्रलयकारी रौद्र रूप की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने को मिल रहीं हैं। प्रकृति से जुड़ी यह ऐसी घटनाएं हैं, जिनको रोख पाना मनुष्य के बस में नहीं हैं। लेकिन इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ज्यादातर मनुष्य ही है। पिछले कुछ दिनों के बीच देश के अधिकांश राज्यों में हुई अतिवृष्ट इसका ताजा उदाहरण हैं जिसके चलते किसानों की खेतों में कटने को तैयार खड़ी खरीफ फसलों में भारी क्षति देखने को मिली है।

पृथ्वी पर रहने अर्थात् अस्तित्व बचाने के लिए मानव, पशु-पंछी, पेड़-पौधे, फसलें आदि की प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भरता होती है। इसलिए कहा जाता है कि कुदरत अर्थात प्रकृति का कानून सर्वोपरि होता है। प्रकृति के मिजाज में जरा सी भी तब्दीली बहुत कुछ उलटफेर कर सकती है। प्रकृति का बदलता प्रलयकारी रूप जहां जीवधारियों के लिए अस्तित्व के विनाश का कारण बन सकता है वहीं फसलों से लेकर पेड़-पौधों और जगलों तक के लिए यह संकट का पर्याय सिद्ध हो सकता है। आज यह विचार सिर्फ अखबारों-किताबों में लिखने-पढ़ने और मानसिक रूप से सोचने मात्र का विषय नहीं रह गया है। अधिकांशत: देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसको देखते हुये यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकृति का बदलता मिजाज खतरे की घंटी बजा रहा है। यदि इसी गति से कुदरत का कहर जारी रहा तो आने वाले समय में इसके घातक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।

इस साल मानसून की शुरूआत कुछ ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही है। जब पूरे देश में किसानों को खरीफ फसलों की बुआई और तैयारी के लिए मानसूनी बरसात की जरूरत थी तब उनके हाथ निराशा ही लगी। लेकिन जैसे तैसे किसानों द्वारा हर संभव प्रयासों के बाद कुछ देरी से ही सही खरीफ फसलों की बुआई की गई। इसके बाद देश के कई राज्यों में सामान्य से कम वर्षा के कारण सूखा के हालात बने तो कई क्षेत्रों में अतिवृष्टी का सामना भी किसानों को करना पड़ा।

उत्तर भारत के अधिकांश राज्य पूरी तरह से खेती-किसानी पर निर्भर हैं। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल से होता है। इसके बाद यह मानसून केरल से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र होता हुआ उत्तर भारत के राज्यों में पहुंचता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में मानसून का आगाज जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए। इससे आगे जाने पर उसे मानसून आने में देरी माना जाता है। कुल मिलाकर देश में मानसून जुलाई से लेकर सितम्बर माह तक सक्रिय रहता हैं। जिसमें जून से लेकर अगस्त माह के अंत तक लगभग 70 प्रतिशत बरसात हो जानी चाहिए।

देश में मौसम विभाग मानसून सक्रिय होने तथा जाने के बाद उसकी विदाई की विधिवत घोषणा करता है। अमूमन उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों से सितंबर के अंत तक मानसून की विदाई की घोषणा हो जाती है। लेकिन इस वर्ष अक्टूबर माह आधा बीत चुका है और मौसम विभाग मानसून की विदाई कोई तारीख तक बता पाने में विवश है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह माना जा रहा है जो कि प्रकृति के बदलते मिजाज की ओर संकेत है। मौसम के बदलाव से बरसात और तापमान का यही ट्रेण्ड चला तो भारत खासकर उत्तर भारत में फसलों के मौसम खरीफ, रबी और जायद में बदलाव होगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रमुख फसलों, उनकी प्रजातियां तथा अन्य गतिविधियों की प्रभावित होगीं।

मानसून के विदाई के समय एक सप्ताह के अंतर पर दो बार अतिवृष्ट होने से किसानों के खेतों में पकने को तैयार तथा पकी खड़ी खरीफ फसलों में भारी नुकसान देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ रबी फसलों की तैयारी के साथ ही सितंबर के अंतिम तथा अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बोई जाने वाले फसलें सरसों, आलू, तोरिया, सब्जी एवं चारा फसलों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। खेतों में अभी तक पानी भरा है। ऐसे में रबी फसलों की तैयार और बुआई में और अधिक विलंब होने के आसार हैं। विलंब की दशा में बुआई करने के कारण यदि मार्च में अधिक तापमान हो गया तो इसका बुरा असर भी होगा।

मानसून की विदाई के समय दो बार हुयी इस अत्यधिक वर्षा से उ.प्र., म.प्र., राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगण, बिहार, उत्तराखण्ड आदि राज्यों में फसलों की बरबादी देखने को मिली है। म.प्र. एवं उ.प्र. जैसे कृषि बहुलता वाले राज्यों में खेतों में खड़ी बाजरा, सोयाबीन, उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली, धान, ज्वार आदि फसलों में 40 से लेकर 70 प्रतिशत तक के नुकसान की खबरें आ रहीं हैं। जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं बाढ़ जो कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। बदलते जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मौसम और पकृति पर आधारित भारतीय कृषि पर पड़ेगा। इसके बाद पशुओं की नस्लें, प्रजनन और उत्पादन पर होगा। इस कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन से लेकर रोजमर्रा की चीजों की कमी होगी और कीमतें बढ़ेगी जिससे गरीब का जीना दुश्वार हो जायेगा।

कम वर्षा दिन और अत्यधिक बरसात किसानों से लेकर मौसम एवं कृषि वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता लकीरें खींच रहे हैं। इसी प्रकार बढ़ते तापमान और सर्दियों के दिनों में कमी होने से उत्तर भारत में रबी फसलों के ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो चुका है। इस वर्ष मार्च माह की शुरूआत में अचानक से तापमान में बढ़ोत्तरी होने और समय से पहले गर्म हवाऐं चलने के कारण गेंहू के उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ा है। गेहूं उत्पादन कम होने के कारण भारत सरकार को इसके निर्यात पर प्रतिबंद जैसा कड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा था। वरना रूस और यूक्रेन संकट के बीच अंतराष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं की काफी मांग थी जिसका भारत कम उत्पादन के कारण लाभ नहीं उठा सका।

बदलते जलवायु परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग के असर के रूप में देखा जा रहा है। पूरे विश्व में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ा रहीं हैं। इस पर काबू पाना संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती है जिससे सभी देशों को मिलकर ही निबटना होगा। हांलाकि इसके पीछे भारत जैसे विकासशील देश की तुलना में विकसित देशों की भूमिका और योगदान बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व पटल वर्ष 2070 तक भारत में ग्रीन हाऊस गैसों पर पूरी तरह से काबू पाने और ग्रीन एनर्जी के शत: प्रतिशत प्रयोग का ऐलान कर चुके हैं। अब समय इस समस्या की जड़ में जाकर चोट करने की है जिससे इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए आम जनमानस से लेकर सरकारों तक को आगे आना ही होगा वरना वक्त निकलते देर नहीं होगी और बाद में शिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं रह जायेगा।

# पुंछकटवा-डेगनाला रोग: लक्षण और बचाव

» डॉ ब्रजमोहन सिंह धाकड़
» डॉ रणविजय सिंह
» डॉ विष्णु गुप्ता
» डॉ भावना गुप्ता
» डॉ प्रदीप कुमार सिंह
» डॉ संजय शुक्ला
» डॉ अजय राय
-पशुचिकत्सा जनस्वास्थय और महामारी विज्ञान विभाग पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि.जबलपुर( मप्र)
-पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तहसील- बरेला, जबलपुर (मप्र)
-पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर(मप्र)
-पशु सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर(मप्र)
-पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर(मप्र)

डेगनाला रोग फफूंदी के विष से होने वाला रोग है। आमतौर पर फफूंदी संक्रमित धान का पुआल खाने से होता है। रोगग्रस्त पशु की टांगों, पूंछ, कान, आदि पर गलन हो जाता है, जो सड़कर शरीर से अलग होने लगते हैं। यह रोग यूजेरियम ट्रिसीक्टंम फफूंदी के विष से होता है। धान की पुआल को ढेर लगाकर रखा जाता है, जिसे यूजेरियम जहर कहते हैं। संक्रमित पुआल खाने से ये रोग होता है।

डेगनाला रोग मुख्यतय: भैंस में देखा गया है। सर्वप्रथम यह रोग पंजाब प्रान्त के डेगनाला नामक नाले के आस-पास बेस क्षेत्रों में देखा गया था। अब यह स्थान पाकिस्तान में है। अधिकांशत: यह रोग नमी वाले क्षेत्रों में होता है। सभी आयु वर्ग के पशु इससे प्रभावित हो सकते हैं। आमतौर पर फफूंद संक्रमित पुआल खाने से ही यह रोग होता है। मगर कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि फफूंद संक्रमित भूसे से भी रोग होता है।

डेग्नाला रोग से ग्रसित पशु कि पूंछ के छोर के बाल खत्म हो जाते हैं व डुडी पुंछ पर गलन होने लगती है। इसी प्रकार कान के किनारे खुर तथा अण्डकोष के किनारों पर भी गलन प्रारम्भ हो जाती है। यह गलन सूखी होती है, जिससे चमड़ी फटने से खुर बाहर निकल जाते हैं। जिससे हड्डी तक दिखायी देने लगती है। जानवर से खड़ा नहीं हो पाता है और कुछ समय बाद ऐसे पशु कि मृत्यु भी हो जाती है।

प्रभावित पशु कि पुंछ अण्डकोष व कानों के किनारे गलन होती है व चमड़ी सूखकर फट जाती है और शरीर से अलग हो जाते हैं व हड्डी दिखायी देने लगती है। ऐसे घाव से खून भी बहता है।

**रोग का निदान:** इसका निदान रोग का इतिहास जानकर व लक्षणों के आधार पर किया जाता है। पुआल का प्रयोगशाला परीक्षण करने पर उसमें फफूंदीजन्य विष की मात्रा व उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। लैब में एच.पी.एल.सी. या एच.पी.टी.एल.सी. विधि से विष का पता लगाया जाता है।

**उपचार:** सामान्यत: इस रोग का कोई उपचार नहीं है। धान के संक्रमित पुआल को चारे के रूप में देना बंद कर देना चाहिए। गलन भरी पुंछ को शल्य क्रिया दवारा काटकर अलग किया जा सकता है। प्रभावित पशु को लवण व विटामिन ए. डी3. इ. एवं सेलेनियम युक्त दवा का उपयोग किया जाए साथ ही प्रोबायोटिक एवं विटामिन बी काम्प्लेक्स का प्रयोग करना चाहिए। घावों को एन्टी सेप्टीक मलहम लगाएं, अधिक समय तक क्रियाशील रहने वाले एन्टी बायोटिक लगाएं, जैसे ऑक्सीटेट्रासीक्लीने-एल. ऐ. बेंजाथील पेनिसिलिन, अमोक्सीसिलिन आदि प्रमुख दवाओं का प्रयोग करें।

**बचाव व रोकथाम:** किसान भाइयों ये तो थी पशुओं में होने वाली बीमारी के कुछ लक्षण एवं उसके बचाव के उपाय अगर आप ज्यादा समझ नहीं पाते तो अपने नियमित पशु चिकत्सक से संपर्क कर भी उपचार करवा सकते है या फिर अपने नजदीक के कृषि विज्ञानं केंद्र में भी जा कर आप वैज्ञानिकों कि सलाह ले सकते हैं जिससे आपके पशुओं के सही समय पर देखभाल भी हो सके साथी ही आपके पशु स्वस्थ भी रह सके किसान भाइयों हम कृषि वाणी का प्रयास है कि आप तक कृषि एवं पशुपालन से जुडी हर जानकारी जो किसान भाइयों के लिए उपयोग में हो आप तक नियमित रूप से उपलब्ध करते रहेंगे आपसे अनुरोध है कि आप इस मुख्य जानकारी को अपने किसान दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सके। बचाव के लिए धान के पुआल को पूरी तरह सुखाकर ही भण्डारित करना चाहि। विशेष रूप से नमी वाले क्षेत्रों में यह ध्यान रखना आवश्यक है। सूखे चारे को पशु को खिलाते समय देख लें कि उसमें फफूंदी तो नहीं लगी है। फफूंदीयुक्त चारे को अलग कर देना चाहिए व जानवर को खाने को नहीं देना चाहिए।

पशुओं को फफूंदी लगा चारा-दाना एवं भूसा न खिलाएं। पुआल को पानी से धोकर खिलाएं। पशुओं को स्वच्छ जगह पर रखें। पशुओं को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर दें। गौशालाओं में नियमित रूप से फिनाईल एवं चूने के पानी का छिड़काव करें। शरीर के संक्रमित भाग को नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर उसी पानी से घाव को साफ करें। किसी भी रासायनिक खेती से उत्पादित फसल से अधिक होती है। कम खर्चे में यदि रासायनिक खेती से थोड़ा कम भी उत्पादन प्राप्त होता है तो भी किसान का आर्थिक रूप से यह लाभ ही देती है, क्योंकि इसमें हजारों रूपए की दवाइयां एवं उर्वरक बचता है, जिससे किसान अपने कम उत्पादन की भरपाई कर सकता है। सब कुछ अपने घर पर ही पैदा होने से कर्ज के बोझ से मुक्ति भी मिल जाती है जिससे जीवन में शांति एवं समृद्धि का आगमन होता है। रायायनिक खेती, जिसे हम बिना सोचे-समझे बढ़ाते है, के अनेक दुष्प्रभाव भी है। यही कारण है कि विश्व के विकसित देश भी पुन: जैविक खेती के महत्व को समझ रहे हैं और इस को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

**जैविक खेती के सिद्धांत:** भूमि में जीवांश की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना। भूमि में सक्रिय जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहन। फसल चक्र में दलहनी फसलों, आवरण फसलों, हरी खाद, अन्तराशस्य फसलों का समावेश। भूमि में अधिक से अधिक केंचुओं की संख्या में बढ़ोतरी। खेतों तथा बागों के चारों तरफ वायु रोधक पौधरोपण को प्रोत्साहन। वायु तथा जल द्वारा क्षरण रोकने हेतु शस्य क्रियाओं के प्रोत्साहन से भूसंरक्षण।

**जैविक खेती की विशेषताएं:** जैविक खाद और रासायनिक खादों का तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुभव करने पर यह पाया गया कि जैविक खाद ज्यादा गुणकारी और लाभकारी है, क्योंकि-

जैविक खाद व कीटनाशी तैयार करने में रासायनिक की तुलना में कम खर्च आता है (लगभग 75-85 प्रतिशत)। जैविक खाद स्थानीय सामग्री से ही तैयार की जाती है। अत: इसकी उपलब्धता ग्राम स्तर पर ही हो सकती है। विघहीन, पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय सामग्री से तैयार होने के कारण ये सुग्राह्य है। जैविक खादों के उपयोग से कृषि उत्पादन निरन्तर बढ़ता जाता है। जैविक खादों के उपयोग से उत्पादित खाद्यात्र, सब्जी, फल, पशुचारा अधिक स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक होता है। ये जैव विविधीकरण व विभिन्नता के सन्तुलित विकास में सहायक होते है। जैविक कृषि उत्पादों की बिक्री व निर्यात में प्रोत्साहन तो मिलता ही है साथ ही इन उत्पादों का बाजार भाव भी 30-40 प्रतिशत अधिक मिलता है। जैविक खाद व कीटनाशी के इस्तेमाल से वायु, जल, मृदा, खाद्यात्र, फल, सब्जी, पशुचारा आदि को प्रदूशण व विषैलेपन से बचाया जा सकता है। जैविक कृषि उत्पादों में भण्डारण क्षमता तुलनात्मक रूप से 30-40 प्रतिशत अधिक होती है।

## फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने तोड़ दी लहसुन किसानों की कमर

भारत सरकार का दावा है कि वह अब तक हुए सभी मुक्त व्यापार समझौतों (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए) की समीक्षा कर रही है। यह तो आने वाले वक्त बताएगा कि समीक्षा में क्या निकलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से किसानों को खेती प्रभावित हो गई। मध्यप्रदेश के नीमच-मंदसौर इलाके में हजारों किसान लहसुन उगाते हैं, लेकिन किसानों के लिए लहसुन उगाना अब फायदे का सौदा नहीं रहा। किसानों को पिछले दो साल से लहसुन की खेती में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार भाव न मिलने के कारण अब लहसुन की खेती से किसानों का मोह भंग होने लगा है। किसानों के अनुसार एक एकड़ लहसुन उगाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। इसमें खाद पर 5 हजार रुपए, बीज पर 7 से 8 हजार रुपए, कीटनाशक पर 3 हजार रुपए और बाकी का मजदूरी पर खर्च आता है। बावजूद इसके हर बार लहसुन में उन्हें नुकसान सहना पड़ता था। जो किसान अपने घर में लहसुन जमा कर रखते हैं, उन्हें ही थोड़ा सा फायदा मिल पाता है। वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान विदेशों से लहसुन का आयात बढ़ रहा है। खासकर, यह लहसुन पेस्ट में पैकिंग होकर बहुत आ रहा है। लहसुन पेस्ट से बाजार पट चुके हैं, जो हमारी लहसुन के मुकाबले काफी सस्ता है, इस वजह से देसी लहसुन की मांग कम हो रही है, जिसका असर कीमतों पर पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि देश में चीन से आने वाले लहसुन पर रोक है, लेकिन चीन से आने वाला लहसुन नेपाल के रास्ते गोरखपुर, रक्सोल के जरिए देश के कई हिस्सों में पहुंच रहा है। कई छोटी भारतीय कंपनियां भी इस सस्ते लहसुन का पेस्ट बनाकर पैक करके बाजार में बेच रही हैं। वैसे भी भारत में दूसरे देशों से लहसुन का आयात बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में भारत ने 4.2 करोड़ टन लहसुन आयात हुआ था। विश्व भर के खाद्य एवं कृषि उत्पादों के आयातकों को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने वाले पोर्टल ट्राइज के मुताबिक लहसुन उत्पादन में चीन के बाद भारत का नंबर दूसरा है, लेकिन पिछले पांच साल के मुकाबले तीन साल के दौरान लहसुन का उत्पादन घटा है और 2018-19 में तो लहसुन के उत्पादन में 1.8 फीसदी कमी आई है।

### कृषि मंत्री मंडी टैक्स का दोहराव और विसंगति को दूर करने का ऐलान किया

# गडकरी ने दिया सुझाव-मप्र में बनाएं सोया नीति, मंत्री पटेल ने भरी हामी

इंदौर। जागत गांव हमार

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र को अपनी अलग से सोया नीति बनाने का सुझाव दिया। इंदौर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोया कान्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि फाइव ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए देश में आयात कम करना होगा। भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। देश में सोयाबीन की उत्पादकता अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों के मुकाबले काफी कमजोर है। गडकरी ने सुझाव दिया कि प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य होने के नाते मप्र को अलग से सोया नीति बनाना चाहिए। मंच पर मौजूद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से गडकरी ने कहा कि इस बारे में विचार करें। पटेल ने मौके पर ही कहा कि सोया नीति बनाने के सुझाव को स्वीकार करते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा होगी। पटेल ने राज्य में उपज पर लग रहे मंडी टैक्स का दोहराव और विसंगति एक सप्ताह में दूर करने का ऐलान भी कानक्लेव के मंच से किया। औपचारिक समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, तुलसी सिलावट, सोपा चेयरमैन डेविश जैन, उपाध्यक्ष गिरीश मतलानी, निदेशक डीएन पाठक के साथ महाराष्ट्र से आए किसान प्रतिनिधि पाशा पटेल भी मंच पर मौजूद थे।

### विदेश से आने वाले खाद्य तेल पर नियंत्रण जरूरी

सोपा के पदाधिकारियों ने मंच से मांग उठाई कि किसानों को सोयाबीन का सही मूल्य मिल सके इसके लिए विदेश से आयात होने वाले खाद्य तेलों की मात्रा पर नियंत्रण जरूरी है। दरअसल, सोपा के पदाधिकारी हाल ही में सरकार द्वारा तीन तरह के खाद्य तेलों का 20 लाख टन आयात शून्य ड्यूटी पर करने के निर्णय को स्थानीय बाजार में सोयाबीन की कीमतें गिरने की वजह बता रहे थे। साथ ही उद्योगों की ओर से मांग की गई कि सोयामील निर्यात पर सरकार को निर्यात इंसेटिव के रूप में कुछ छूट या राहत देना चाहिए। इससे भारतीय सोयामील विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगा। निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।

### सोया प्रोटीन का उपयोग देश में हो

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में प्रति एकड़ सोयाबीन 26 से 30 क्विंटल होती है, हमारे यहां सिर्फ पांच क्विंटल पैदावार होती है। ऐसे में उन्नत बीजों के विकास पर ध्यान देना होगा। इसमें सरकार के साथ सोपा जैसी संस्थाओं को भी सहभागी बनना चाहिए। आयात कम करने के लिए यह जरुरी है। सोयाबीन के आटे में 49 प्रतिशत प्रोटीन होता है। देश के लोगों को पोषण की जरूरत है। मैं खुद अंधेरी से सेंव लाता हूं जो सोया आटे से बनी होती है। ऐसे खाद्य उत्पादों के विकास पर मप्र जैसे सोया प्रदेशों को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अब कृषि उपजों से ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। किसान न केवल अन्नदाता बल्कि उर्जा प्रदाता भी बन सकें। देश में सोयाबीन का उत्पादन प्रति एकड़ 15 क्विंटल से ऊपर जाए इस दिशा में सोया नीति बनाकर मप्र को अगुवाई करना चाहिए।

### तो किसान उगाने लग जाएंगे बांस

महाराष्ट्र के किसान नेता पाशा पटेल ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि अगर सोयाबीन की कीमतें सही नहीं मिली तो किसान सोयाबीन उगाना छोड़कर बांस उगाने पर जोर देगा। महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा था। उन्होंने कहा कि देश में प्रति एकड़ सोयाबीन का उत्पादन दो से तीन क्विंटल से ज्यादा नहीं है जबकि विदेशों में 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन है। विदेशी जीएम सोयाबीन से मुकाबले देश का नाम जीएम सोयाबीन तब ही कर सकता है जबकि सरकार एक्सपोर्ट इंसेटिव है। सोपा ने विभिन्न मांगों के साथ अगले महीने तेल आयात पर नियंत्रण और अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की बात भी कही।

### एक सप्ताह में निर्णय

प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकारी खरीदी के उदाहरण देते हुए कहा कि गडकरीजी के सोया नीति पर सरकार आगे बढ़ेगी और जल्द ही मुख्यमंत्री से मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि तेल आयात पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंत्री गोयल से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में मैं, मंत्री सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा मंडी टैक्स के दोहराव और दरों पर राहत देने का निर्णय एक सप्ताह में ले लिया जाएगा।

### सोपा के चेयरमैन देविश जैन ने कान्क्लेव में किया दावा

# नान जीएम सोयाबीन में भारत बन जाएगा ब्रांड

» सोया उद्योगों ने मांगी निर्यात नीति में राहत

» इंदौर में दो दिनी अंतरराष्ट्रीय सोया कान्क्लेव की शुरुआत

इधर, कोविड के दौर के बाद बदले परिदृश्य में सोयाबीन का व्यापार भी कठिन दौर से गुजर रहा है। भारत से सोयामील का निर्यात लगभग थम गया है। अंतरराष्ट्रीय सोया कान्क्लेव की शुरुआत करते हुए दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा) के चेयरमैन देविश जैन ने यह बात कही। इंदौर में दो दिनी कान्क्लेव के उद्घाटन अवसर पर सोया इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगों ने मांग रखी कि सरकार को सोयामील निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क, परिवहन खर्च में छूट देनी चाहिए।

सोया उद्योगों की ओर से वर्तमान की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर बात रखते हुए सोपा ने कहा कि बीते दो वर्ष सोया उद्योगों के लिए मुश्किल भरे रहे। देश में सोयाबीन की कीमतें उच्चतम स्तर पर जाने के चलते निर्यात रुक गया। जैन ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार सरकार सोयामील निर्यात पर इंसेंटिव नहीं दे सकती, लेकिन देश के निर्यातकों को देश के भीतर ही सोयामील परिवहन की लागत अंतरराष्ट्रीय फ्रेट भाड़े से ज्यादा पड़ती है। 9 से 10 प्रतिशत के अन्य घरेलू शुल्क व खर्च सोयामील की लागत में जुड़ रहे हैं। सरकार को फ्रेट शुल्क और आंतरिक खर्च टैक्स पर छूट देनी चाहिए। यदि सरकार राहत देती है तो मौजूदा परिस्थिति में सोयामील का निर्यात 40 लाख टन तक हो सकता है। इससे दो बिलियन डालर देश में आएंगे।

### उत्पादन बढ़ेगा

सोपा के अनुसार, देश में सोयाबीन का उत्पादन 120 से 125 लाख टन रहने की उम्मीद है। 2025 तक उत्पादन का आंकड़ा 160 लाख टन और 2030 तक दो करोड़ टन तक पहुंच सकता है। बशर्ते सरकार सोयाबीन उपजाने के लिए किसानों को, निर्यात के लिए उद्योगों को राहत दे। सोपा ने कहा कि देश में अब भी प्रति हेक्टेयर सोयाबीन उतपादन कम है। ऐसे में देश में किसानों को अच्छा बीज सरकार द्वारा पहल कर उपलब्ध करवाने की जरूरत है। किसानों को अच्छे दाम मिले, इसलिए खाद्य तेल के निर्यात की मात्रा पर नियंत्रण की जरूरत है। सोपा ने सरकार द्वारा हाल की में देश में 0 प्रतिशत शुल्क पर आयात किए तीन तरह के खाद्य तेलों के आयात की निर्णय को उद्योगों और किसानों के लिए प्रतिकूल बताया।

### नान जीएम की ब्रांडिंग करें

सोपा ने कहा कि सिर्फ भारत समेत कुछ ही देश है जो नान जीएम सोयाबीन उगाते हैं। इसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। सरकार को ब्रांड इंडिया फंड के तहत नान जीएम सोया को देश यूएसपी बनाकर ब्रांडिंग करना चाहिए। सोपा ने एलान किया कि जल्द ही सोपा एल क्वालिटी सील लांच करेगा। सोयाबीन तेल व उत्पादों का परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर सोपा की सील रहेगी। ताकि देश के उपभोक्ताओं को सही उत्पाद मिल सके।

### कृषि मंत्री ने कहा-उन्नत कृषि में कृषि विशेषज्ञता का मिलेगा लाभ

# कृषि शिक्षा की सार्थकता तभी जब सीमांत किसानों में आए खुशहाली

» राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि में हुआ 8वां दीक्षांत समारोह

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजमाता सिंधिया कृषि विवि के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को लाभ और सीमांत किसान परिवारों की खुशहाली में ही कृषि की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही विद्यार्थी प्राप्त की गई शिक्षा से अपने परिवार के साथ सम्पूर्ण समाज के कल्याण में योगदान देंगे। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि संकाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ कृषि को उन्नत बनाने में मिलेगा। दीक्षांत समारोह में चार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 14 को शोध उपाधियां (पीएचडी) सहित 321 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 303 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही तीन विद्यार्थियों को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।

### यह रहे मौजूद

दीक्षांत समारोह में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह, विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. आरसी अग्रवाल, कृषि विवि के कुलपति प्रो. एसके राव राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विवि के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी, कृषि विवि के डीन डॉ. दीपक हरी रानाडे, अधिष्ठाता एनएस भदौरिया सहित विवि प्रबंध मंडल के सदस्य और विद्यार्थी मौजूद थे।

### कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ें

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया की सब खेती को समावेशी, व्यापक और अधिक टिकाऊ बनाने में पूरे उत्साह के साथ योगदान देंगे। कृषि विद्यार्थियों के प्रयास ऐसे हों, जिससे देश में कृषि व्यापार का ऐसा वातावरण बने जो किसानों के लिए लाभकारी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्यपाल ने जैविक खेती अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को उपयुक्त तकनीक और खेती के नए-नए तरीकों में पारंगत करने की जरूरत है। साथ ही यह भी प्रयास करने होंगे कि किसान कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ें।

### फंड से किसानों को मिल रही मदद

कृषि मंत्री कमल पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि कृषि की पढ़ाई की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब कृषि विशेषज्ञता का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि और कृषि अधोसंरचना विकास फंड से किसानों को बड़ी मदद मिल रही है। कृषि मंत्री ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी ओर से 10-10 हजार रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की।

### उत्पादन बढ़ाने में दें योगदान

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि कृषि विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान दें और जलवायु परिवर्तन अप्रभावित होने वाली ऐसी कृषि तकनीकें खोजें जिससे सूखे और अतिवर्षा की स्थिति में भी किसानों को अच्छा उत्पादन मिल सके। कुशवाह ने कहा कि कृषि विद्यार्थी किसानों को उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित करें।

## मृत गौवंश को दफना रहा निगम, पशु विभाग अनजान, चंबल के आठ जिलों में 9 गाय लंपी की चपेट में

# चंबल अंचल में निराश्रित गायों पर टूटा लंपी का कहर

सोमराज मौर्य। ग्वालियर/शिवपुरी

लंपी वायरस निराश्रत गाय पर कहर ढा रहा है। लंपी की चपेट में आने से गौवंश काल के गाल में समा रहा है। नगर निगम का अमला हर दिन एक सैंकड़ा गौवंश के मृत शरीर को लेंडफिल साइड पर दफना रहा है। गायों की मौत का कारण लंपी वायरस बताया जा रहा है। लेकिन गाय की मौत की खबर से पशु विभाग अनविज्ञता जता रहा है। जबकि पिछले एक सप्ताह में पांच सैंकड़ा से अधिक गौवंश दफनाने की बात निगम का अमला बोल रहा है। लेकिन पशु विभाग अपनी रिपोर्ट में केवल लंपी वायरस से पीड़ित जानवरों की जानकारी ही बता रहा है, जबकि लंपी से मौत की संख्य अब तक ग्वालियर चंबल अंचल को मिलाकर महज 27 पर अटका हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में लंपी वायरस की चपेट में आठ जिलों में 90 गाय बताई गई हैं। जिसमें ग्वालियर जिले में 52 गाय आई हैं।

### इन्हें मिला नोटिस

पशु विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. अशोक तोमर ने बताया कि चार शहर का नाका पर तैनात डॉ. बीके शर्मा ने पशु पालक को गलत जवाब देते हुए कहा कि वह लंपी का इलाज करने में असमर्थ है। जिसे वीडियो भी बहुप्रसारित हुआ। इसके साथ ही लश्कर पोलीक्लीनिक पर तैनात असिस्टेंट वेटनरी फील्ड आफिसर डॉ. अमित गुप्ता ने कहा कि निराश्रत गौवंश का इलाज नहीं दिया जा सकता। इस तरह के कथन देने वाले दोंनो डाक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि इस तरह के जबाव यह नहीं दे सकते यह अनुशासनहीनता है। इसके साथ ही डॉ. तोमर का कहना है कि लंपी से गौवंश की मौत हो रही है तो इस मामले में नगर निगम को पशु विभाग को सूचना देना चाहिए जिससे मौत के कारण का पता लगाया जा सके।

**क्वारंटाइन सेंटर गौवंश से भरे**| अंचल के अन्य जिलों में लंपी का कहर कम हो रहा है तो ग्वालियर जिले में बढ़ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर गौवंश से भर चुके हैं और निराश्रत गौवंश को ठीक से उपचार नहीं मिल पाने से मौत के शिकार बन रहे हैं। हालांकि पशु विभाग के संयुक्त संचालक ने दो डाक्टरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन्होंने लंपी का उपचार देने में खुद को असमर्थ बताया था जिसका वीडियो भी बहुप्रसारित हुए था।

### कहां पर कितने लंपी के शिकार

| | |
|---|---|
| ग्वालियर | 52 |
| दतिया | 00 |
| शिवपुरी | 22 |
| गुना | 00 |
| अशोकनगर | 07 |
| भिंड | 02 |
| मुरैना | 12 |
| श्योपुर | 02 |

# महिला कृषकों का किया गया सम्मान

सागर। जागत गांव हमार

महिला किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर द्वारा प्रशिक्षण एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 50 महिला कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या अहिरवार, विकास खण्ड बण्डा ने किया। इस कार्यक्रम में सागर, बण्डा, खुरई आदि ब्लॉक से विभिन्न गांवों की महिलाएं शामिल हुईं। इन सभी कृषक महिलाओं को सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर केन्द्र प्रमुख डॉ. के.एस.यादव ने महिला सशक्तीकरण, उनके अधिकारी, महिलाओं की कृषि में प्रमुख भूमिका के साथ- साथ किचिन गार्डन एवं उसके विभिन्न पोषक तत्वों का महत्व, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, प्राकृतिक एवं जैविक खेती आदि विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. वैशाली शर्मा एवं डॉ. यादव द्वारा केन्द्र की विभिन्न इकाईयों जैसे एजोला यूनिट, मुर्गीपालन इकाई, केंचुआ इकाई, नर्सरी इकाई, पोषक तत्वों से युक्त कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना आदि के जीवंत क्राप कैफेटेरिया का भ्रमण तथा उसके महत्व से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्यक्रम प्रभारी डॉ. वैशाली शर्मा का प्रमुख योगदान रहा।

### महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं

**टीकमगढ़।** कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ द्वारा महिला कृषकों के सशक्तिकरण के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे जिले में महिला कृषकों का आर्थिक रूप से उत्थान हो रहा है।

राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख अतिथि विवेक चतुर्वेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष मध्यांचल ग्रामीण बैंक टीकमगढ़, ने कहा की महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने महिला समूहों को सहायता करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विवि, झाँसी के प्रबंध मंडल सदस्य आराधना श्रीवास्तव ने महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आकर परिवार की आय बढ़ाने में सहायता करने हेतु प्रोत्साहित किया साथ ही केन्द्रीय विष्वविद्यालय झांसी से टीकमगढ़ जिले के किसानों के लिये परियोजना लाने का प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़, डॉ. व्ही. के. सिंह द्वारा महिलाओं को कृषि में भागीदारी को बताया तथा सामान्य फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों, सब्जियों आदि फसलों को कुछ हिस्से में खेती करने पर जोर दिया । तकनीकी सत्र में डॉ. बी. एस. किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख ने अपने उदबोधन में सभी कार्यक्रम मे सम्मिलित सभी महानुभावो एवं जिले से 150 महिला कृषकों का स्वागत किया और कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा महिला सशक्तिकरण में किये जा रहे कार्यो की उपलब्धियों को बताया।

## महिला किसान दिवस पर कार्यक्रम

# जगत की प्रथम कृषक महिला डॉ. किंजल्क सी. सिंह

रीवा। जागत गांव हमार

प्रागैतिहासिक काल से धरती की जगत जननी तथा प्रथम कृषक स्त्री को ही माना गया है। स्त्री के स्वभाव में ही पोसना है। अत: यह देखा गया है कि जिस खेत में स्त्री कृषि कार्य में हाथ बंटाती है उस खेत में उत्तरोत्तर कृषि प्रगति के पथ पर नये आयाम तय करती है। उक्त विचार डॉ. किंजल्क सी. सिंह, वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) के हैं जो कि शासकीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति जनजाति कन्या छात्रावास में कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा (म.प्र.) द्वारा आयोजित महिला किसान दिवस में 40 प्रतिभागियों को, मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित कर रही थीं।

ग्रामीण अंचल की छात्राओं के माध्यम से माताओं बहनों को परिवार की धुरी ठहराते हुये उनके स्वस्थ्य रहने को अत्यावश्यक बताया जिसके लिये पौष्टिक भोजन का सेवन महत्वपूर्ण कुंजी है।

उक्त कार्यक्रम, संचालक विस्तार सेवायें, डॉ. दिनकर शर्मा के निर्देशन में तथा कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. अजय कुमार पांडेय तथा कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस. के.प्यासी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया जिसमें डॉ. अखिलेश पटेल, वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान), डॉ. राजेश सिंह, वैज्ञानिक (उद्यानिकी), डॉ. बृजेश कुमार तिवारी, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान), डॉ. अखिलेश कुमार, वैज्ञानिक (पौध संरक्षण), डॉ. स्मिता सिंह, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान), डॉ संजय सिंह, वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), डॉ. केवल सिंह बघेल, वैज्ञानिक (पौध रोग), मृत्युंजय मिश्रा आदि का सहयोग रहा।

# महिला किसानों का किया सम्मान

**बैतूल।** महिला किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार, बैतूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आंगनवाड़ी एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। केन्द्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. वही.के. वर्मा ने महिलाओं को कृषि कार्यों के साथ-साथ पोषण आहार के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर केन्द्र प्रमुख द्वारा महिला किसानों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया। कार्यक्रम में डॉ. मेघा दुबे ने कृषक महिलाओं को मुनगा एवं मोटे अनाज के पौष्टिक तत्वों एवं व्यंजनों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एम.पी. इंगले ने किया एवं इस कार्यक्रम में केन्द्र के सभी वैज्ञानिक आर.डी. बारपेटे, डॉ. एस.एस. गौतम, डॉ. संजय जैन आदि सक्रिय रूप से शामिल हुए।

## रावे छात्राओं ने स्वच्छता अभियान में किया जागरुक

सागर। जागत गांव हमार

स्वच्छता अभियान-2022 के अंतर्गत रावे छात्राओं द्वारा ग्राम बदौना में स्वच्छता की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. केएसयादव, डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशली शर्मा और डॉ. डीपी सिंह के मार्गदर्शन में कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा की छात्राओं ने स्वच्छता रैली निकाली। साथ ही साफ-सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया जिसमें छात्राओं के साथ-साथ गांव के किसान भी मौजूद रहे। गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। जैसे नारे लगाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया।

# कम खाद से अधिक पैदावार का जगाया अलख

**छात्राओं न बताया कैसे बनाएं नीमास्त्र**| आज के समय में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा से आयी हुई छात्राओं द्वारा ग्राम बदौना में मृदा वैज्ञानिक डॉ. वैशाली शर्मा व डॉ. केएस यादव के मार्गदर्शन में किसानों को नीम की पत्तियों की सहायता से नीमास्त्र बनाना सिखाया। जिससे उर्वरकों का उपयोग कम होगा और फसल की पैदावार बढ़े इस अवसर पर ग्राम के किसान मौजूद रहे।

### जागरूकता सप्ताह मनाया

कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर में कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा से आयी हुई छात्राओं द्वारा ग्राम बदौना में किसानों को जल स्वच्छता के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान रावे छात्राओं ने गांव के पानी के टैंकर में ब्लीचिंग पाउडर डाला और किसानों को अषुद्ध जल से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान की। छात्राओं ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. के.एस.यादव तथा रावे प्रभारी डॉ. वैशाली शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया।

### छात्राओं ने किया पौधरोपण

छात्राओं द्वारा ग्राम बदौना में पर्यावरण के प्रति लोगों का जागरूक करने के उद्देष्य से गांव के स्कूल, आंगनवाडी एवं मंदिर के पास पपीता, नीम, सीताफल, आंवला आदि पौधों का रोपण किया। इस दौरान आंगनवाडी की प्रमुख दुर्गा बाई पटेल एवं सहायक कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

### केंद्रीय मंत्री तोमर बोले-11 हजार करोड़ खर्च, आयल पाम मिशन शुरू

# दस हजार नए एफपीओ से छोटे किसान हो जाएंगे आत्मनिर्भर

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तिलहन में आयात निर्भरता कम करने के लिए 11 हजार करोड़ रुपए के खर्च से आयल पाम मिशन शुरू किया गया है। देश में 28 लाख हेक्टेयर भूमि आयल पॉम की खेती के लिए अनुकूल है। पूर्वोत्तर में अनुकूलता ज्यादा है। गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का प्रावधान किया गया है। पशुपालन, मत्स्यपालन, औषधीय खेती के लिए भी विशेष पैकेजों का प्रावधान किया गया है। तोमर ने यह बात एसोसिएटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसौचेम) द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और कृषि सामग्री एकीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली कही। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश आसानी से पार पा सकता है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र ने यह करके दिखाया है। देश के 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की, साथ ही मित्र देशों की मदद भी की। आज अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में हम दुनिया के पहले या दूसरे स्थान पर हैं। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। कृषि उन्नत खेती में बदले, कृषि में टेक्नालॉजी का प्रयोग हो व इसकी निरंतरता बनी रहे, इस दिशा में काम करने की जरूरत है।

## बिचौलियों का दखल होगा खत्म

तोमर ने कहा कि किसानों और बाजार के बीच की दूरी कम करने, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, बिचौलियों का दखल खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास छोटा रकवा है व निवेश के लिए राशि नहीं है। ऐसे किसानों के लिए केंद्र सरकार 10 हजार नए एफपीओ बना रही हैं, जिनके लिए 6,865 करोड़ का प्रावधान किया है और छोटे-छोटे किसानों को जोड़ा जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसान समूह में खेती करें, जिससे आदान की लागत कम आए, उत्पादन गुणवत्ता को सुधारा जा सके, छोटे किसान महंगी फसलों की ओर जा सकें व अपनी शर्तों पर उपज मूल्य प्राप्त कर सकें। एफपीओ उत्पादों की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए बिना गारंटी के दो करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था सरकार ने की है।

## कृषि क्षेत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा

तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र जितना मजबूत व फायदेमंद होगा, देश उतना मजबूत होगा। आज कृषि के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर विचार करने की जरूरत है। सभी तरह की अनुकूलताओं के बाद भी कृषि का क्षेत्र और उसकी लाभ-हानि प्रकृति पर काफी निर्भर करती है। खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता व लगाव बढ़ना चाहिए। खेती अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक हो और खेती करने वालों को खेती के लिए रोका जा सके, इस दिशा में और अधिक काम करने की जरूरत है।

## नुकसान का आंकलन तकनीक से करेंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी भारत सरकार काम कर रही है, जिससे किसान, बैंक व अन्य संस्थान जुड़े रहेंगे। क्रॉप आंकलन व जानकारी एकत्रित करेंगे, नुकसान का आंकलन भी तकनीक से किया जाएगा। इस प्रकार मैपिंग की जाएगी कि राज्य सरकारों के माध्यम से देशभर के किसानों को एडवाइज किया जा सके कि कहां-किसकी खपत है, तो इतना उत्पादन किया जाकर लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे अफरातफरी नहीं रहेगी, नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है, इस दिशा में हम सबको आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में एसोचैम के महासचिव दीपक सूद, असगर नकवी, जय श्रॉफ मौजूद थे। इस मौके पर नालेज पेपर का विमोचन किया गया।

### जनेकृविवि के विद्यार्थियों एवं खाद्य वैज्ञानिकों की पहल

# हर घर महकेंगे कोदो कुटकी के बने व्यंजन

जबलपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन के नेतृत्व में एवं कृषि कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. पीबी शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एसएस शुक्ला के निर्देशन में खाद्य विज्ञान विभाग के छात्र-छात्राओं एवं वैज्ञानिकों के प्रयास से जवाहर आउटलेट में क्रॉलिटी प्रोड्क्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की विशेष फसल कोदो-कुटकी, सांवा जो सुपर फूड के नाम से जाने जाते हैं। पूर्ण गुणवत्ता के साथ उपलब्ध की जा रही हैं। विभागाध्यक्ष डॉ. शुक्ला ने बताया कि जवाहर फूड्स आउटलेट में उत्तम गुणवत्ता एवं पौष्टिक उत्पाद की सौगात के रूप में 28 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोदो राईस, कुटकी राईस, रागी फ्लोर, सरगम पास्ता, रागी पास्ता, कोदो पास्ता की बहुत डिमांड हैं। एमपी के माईनर मिलेट का जायकेदार व्यंजनों का स्वाद व लुफ्त उठाने के लिए गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। मंडला एवं डिंडोरी के आदिवासियों की लोकप्रिय फसलों द्वारा तैयार जैसे कोदो की खीर, भात और हलवे का व्यंजन के रूप में लोकप्रिय है। कोदो के व्यंजन में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और एण्टी आक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

## कोदो-कुटकी एक सुपरफूड-फायदे

यह ग्लूटन-फ्री होता है। पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोदो की मांग बढ़ी है। इसे शुगर फ्री चावल के नाम से जाना जा रहा है, इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद रहता है। कोदो मिलेट में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैगनिज, कैल्शियम, थायामिन, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर तथा रिबोफ्लेविन पाए जाते हैं। इन माइनर मिलेट्स के अनेकानेक फायदे हैं जैसे-वजन घटाने में फायदेमंद, ग्लूटेन फ्री अनाज, डायबिटीज रिवर्स करने में मददगार, ह्रदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, कैंसर में फायदेमंद, एंटी माइक्रोबियल, बेहतर नींद के लिए, रक्त साफ करने में सहायक, पेट सम्बन्धी समस्यायें दूर होती है, लिवर को स्वस्थ रखता है, किडनी को स्वस्थ रखता है, घाव भरने मे सहायक, बच्चों के लिए भी फायदेमंद, इसके अलावा अन्य उत्पाद जैसे- कुकिज, मफिंस , बिस्किट, जवाहर पोहा, जवाहर मुरमुरा, जवाहर रोस्टेड चना, वेज पास्ता, सारगम, पास्ता के अलावा चॉकलेट, टोमेटो प्रोडक्ट्स, जेम, जेली आदि की उपलब्धता आम जनमानस को बेहतर उत्पाद व उत्तम स्वास्थ्य के लिए कारगर हैं।

# प्रदेश में किसानों को नकद में मिलेगी खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में किसानों को खाद मिलने में हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने कमजोर वित्तीय स्थिति वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को और कालातीत समितियों के नियमित किसानों को नकद में खाद विक्रय करने का निर्णय लिया है। सहकारिता विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नियमित सदस्यों के साथ-साथ समय पर ऋण न चुकाने वाले कालातीत सदस्यों को भी नकद में खाद दी जाए। यह व्यवस्था केवल ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, होशंगाबाद और हरदा जिले में रबी सीजन 2022-23 की शेष अवधि के लिए लागू होगी। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने कलेक्टर को दिए निर्देश में कहा कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और कालातीत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के नियमित किसानों को नकद में खाद देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सहकारी विपणन संघ से खाद लेने के बाद राशि न देने के कारण समितियां कालातीत हो गई हैं। इन्हें खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने मार्कफेड से उधार में खाद दिलाने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी मार्कफेड के नकद विक्रय केंद्रों पर लग रही किसानों की भीड़ को देखते हुए नकद में खाद का

### सिलावट बोले-युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, कार्यशाला में पांच देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए

# मत्स्य पालन में निवेश की असीम संभावनाएं

इंदौर। जागत गांव हमार

मप्र में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पांच देशों तथा आठ राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादकों, मत्स्य पालकों एवं मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।

प्रदेश के जल संसाधन तथा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कार्यशाला में कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मछली पालन क्षेत्र का अहम योगदान है। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। मत्स्य पालकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सिलावट ने कहा कि प्रदेश में मछली पालन विभाग के नवाचारों से मछुआ समाज के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। देश में अब नीली क्रांति की शुरुआत प्रदेश से होगी। मत्स्य बीज उत्पादन और मछली उत्पादन के साथ इसकी प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी प्रदेश में निवेश हो रहा है और अभी इस क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में निवेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीठे पानी की मछली के निर्यात का बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर मछुआरों और मछली पालक की आय में वृद्धि भी होगी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि केन्द्र सरकार

द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआरों के समग्र कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। केन्द्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

## एमओआई भी साइन किए

प्रमुख सचिव मत्स्य पालन कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला में पांच देश जिसमें जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरीशस तथा नेपाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के साथ एमओआई भी साइन किए हैं। इससे प्रदेश में मछली उत्पादन के साथ मार्केटिंग और निर्यात की नई संभावना पैदा होंगी।

## आठ राज्यों के विभागीय अफसर भी आए

कार्यशाला में 5 देशों तथा आठ राज्यों के प्रतिनिधि और देश के 8 से अधिक राज्यों के मछली विभाग के संचालक भी शामिल हुए। कार्यशाला में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की आर वनिता तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के संचालक विजय कुमार भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश शासन
आज़ादी का अमृत महोत्सव

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अब स्वच्छता में भी
मध्यप्रदेश नम्बर 1

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन
मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास
और
आपका सहयोग
धन्यवाद मध्यप्रदेश

देश में लगातार छठवीं बार नंबर वन स्वच्छ शहर इंदौर

85 प्रतिशत (323) नगरीय निकाय ओडीएफ++ से प्रमाणित

स्वच्छता में प्रदेश के 99 शहरों को स्टार रेटिंग से किया गया प्रमाणित

स्वच्छता में प्रदेश को मिले कुल 16 राष्ट्रीय अवॉर्ड

1 लाख से अधिक जनसंख्या के टॉप 100 शहरों में हमारे 30 शहर शामिल

1 लाख से कम जनसंख्या के टॉप 100 शहरों में हमारे 19 शहर शामिल

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-19455/22
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2022

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)